

# भारत में बाल कुपोषण की गंभीर समस्या

डॉ. राम प्रताप गुप्ता

बच्चों को हर राष्ट्र अपनी सर्वाधिक मूल्यवान संपदा समझता है और उनके समुचित पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था करता है। हर राष्ट्र इनकी व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने लगा है। ऐसा करके ही राष्ट्र अपने वर्तमान और भविष्य की खुशहाली सुनिश्चित करते हैं। इन्हीं तथ्यों की पृष्ठभूमि में विश्व के राष्ट्रों ने अपने सहस्त्राब्दी लक्ष्यों में कुपोषित बच्चों की संख्या को कम करके आधा करने के लक्ष्य को भी शामिल किया है।

भारत इन दिनों विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होने के साथ ही सन 2020 तक विश्व की महाशक्तियों में शामिल होने की आकांक्षा पाल रहा है। उसकी यह आकांक्षा तभी साकार होगी जबकि उसकी मानव संपदा की बेहतरी की प्रक्रिया निरंतर बनी रहे। इस समय कुपोषित बच्चों के प्रतिशत की दृष्टि से विश्व के राष्ट्रों में भारत का स्थान सबसे ऊपर है। मानव विकास प्रतिवेदन सन 2005 के अनुसार केवल नेपाल, बांग्लादेश और इथियोपिया ही ऐसे राष्ट्र हैं जहां कुपोषित बच्चों का प्रतिशत भारत की तुलना में अधिक है।

देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों के पोषण की इतनी उपेक्षा भारत जैसे राष्ट्र के लिए कलंक ही माना जाएगा। बच्चों के पोषण की व्यवस्था की दृष्टि से भारत अफ्रीकी राष्ट्रों से भी पीछे रह गया है। यहां इस तथ्य को भी दोहराना आवश्यक है कि शरीर वैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक संभावनाओं का 90 प्रतिशत विकास 3 वर्ष तक की आयु में ही सुनिश्चित हो जाता है। अतः इस आयु के बच्चों को समुचित पोषण मिलना ही चाहिए। बाद की आयु में हम कितना ही अच्छा पोषण प्रदान करें, उसका अधिक महत्व नहीं रह जाता है।

पिछले कुछ वर्षों से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोपुलेशन स्टडीज़, मुम्बई कुछ अन्य संस्थाओं और भारत सरकार के सहयोग से परिवार स्वास्थ्य सर्वे करता रहा है। ऐसे तीन सर्वे क्रमशः

तालिका 1  
भारत में कुपोषित बच्चों का प्रतिशत

राज्य का नाम	1992-93	1998-99	2005-06
1. केरल	27.0	26.9	28.8
2. हरियाणा	34.6	34.6	41.9
3. हिमाचल	43.7	43.6	36.2
4. राजस्थान	44.2	50.6	44.0
5. आंध्रप्रदेश	45.0	37.7	36.2
6. तमिलनाडु	45.7	36.7	33.2
7. पंजाब	46.0	28.7	27.0
8. उत्तरप्रदेश	47.7	51.7	47.3
9. उत्तराखण्ड	-	37.9	36.5
10. गुजरात	48.1	45.1	47.4
11. मध्यप्रदेश	48.5	55.1	60.3
12. छत्तीसगढ़	-	60.9	52.1
13. असम	49.3	36.0	40.4
14. कर्नाटक	50.6	43.9	41.1
15. महाराष्ट्र	51.4	49.6	39.7
16. उड़ीसा	52.4	54.0	44.0
17. प. बंगाल	54.8	48.7	43.5
18. बिहार	62.5	54.3	58.4
19. झारखण्ड	-	54.3	59.2
20. संपूर्ण भारत	51.5	47.0	45.9

1992-93, 1998-99 और 2005-06 में किए जा चुके हैं। इन सर्वेक्षणों के माध्यम से राष्ट्र और राज्य स्तर पर बाल कुपोषण के प्रतिशत के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध हुए हैं जो राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो के आंकड़ों से मिलते-जुलते हैं।

सामाजिक-आर्थिक विकास के स्तर की दृष्टि राज्यों में काफी विविधता है। अतः इन राज्यों में बाल कुपोषण की स्थिति और पिछले वर्षों में उसमें आए परिवर्तनों का अध्ययन भावी नीतियों के निर्धारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तालिका-1 में 1992-93, 1998-99 और 2005-06 में देश के प्रमुख राज्यों में बाल कुपोषण के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1992-93 में देश में कुपोषित बच्चों का प्रतिशत 51.5 था जो कि वर्ष 1998-99 तक गिरकर 47 प्रतिशत रह गया था। इस अवधि में कुपोषित बच्चों के प्रतिशत में 4.5 प्रतिशत की कमी हुई

अर्थात् कुपोषित बच्चों की संख्या में 0.75 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से कमी हुई। कुपोषित बच्चों के प्रतिशत में कमी की यह दर आगे के वर्षों में कायम रही तो भी हम सहस्राब्दि लक्ष्यों के नज़दीक नहीं पहुंचते। वर्ष 1998-99 में कुपोषित बच्चों का प्रतिशत 47 से गिरकर वर्ष 2005-06 में केवल 45.9 प्रतिशत तक ही पहुंच सका। दूसरे शब्दों में इस अवधि में कुपोषित बच्चों के प्रतिशत में नाममात्र की (0.16 प्रतिशत प्रतिवर्ष) कमी हुई। ऐसे में अगर हम अब सहस्राब्दि विकास लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो बाल कुपोषण के क्षेत्र में कमी लाने के प्रयास युद्धस्तर पर करने होंगे। वर्तमान में इस दृष्टि से चलाए जा रहे कार्यक्रम एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम की उपलब्धियां अब तक नहीं के बराबर ही रही हैं। हमारे तीव्र गति से विकास का भी बाल कुपोषण में कमी की दृष्टि से कोई अर्थ नहीं है क्योंकि 1998-99 से 2005-06 की अवधि में 1992-93 से 1998-99 की अवधि की

## तालिका 2

देश के विभिन्न राज्यों में बाल कुपोषण का वर्ष 1992-93 का स्तर एवं उसमें प्रतिशत कमी

कुपोषण (%) (1992-93)	कुपोषण स्तर में कमी (प्रतिशत)					
	- 8 से अधिक	- 8 से - 4	- 4 से 0	0-4	4 से 8	8 से 12
25-30	-	-	केरल	-	-	-
30-35	-	हरियाणा	-	-	-	-
35-40	-	-	-	उत्तराखंड	-	-
40-45	-	-	-	राजस्थान	हिमाचल	-
45-50	-	-	-	गुजरात उ.प्रदेश	-	असम आंध्र
50-55	-	-	-	-	भारत	महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा
55-60	-	झारखंड	-	-	-	-
60 से अधिक	-	-	-	-	बिहार	छत्तीसगढ़

1. झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तरांचल के आंकड़े वर्ष 1998-99 से 2005-06 के बीच बाल कुपोषण में कमी के है।
2. मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश एवं बिहार के वर्ष 1998-99 एवं 2005-06 सम्बंधित आंकड़े विभाजन के पश्चात के है।

तुलना में विकास दर कहीं अधिक रहते हुए भी बाल कुपोषण में कमी की दर गिर गई है।

तालिका-1 में बाल कुपोषण के राज्य स्तरीय आंकड़े भी दिए गए हैं। इसी अवधि में मध्यप्रदेश को विभाजित कर छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश को विभाजित कर उत्तरांचल और बिहार को विभाजित कर झारखंड का निर्माण भी किया गया। अतः वर्ष 1992-93 और 2005-06 के आंकड़े विभाजित एवं नवनिर्मित राज्यों के लिए अलग-अलग दिए गए हैं। वर्ष 1992-93 में सबसे कम बाल कुपोषण वाले प्रथम 5 राज्यों (केरल, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और आंध्र) में केवल हरियाणा ही प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से विकसित राज्य हैं। अन्य राज्यों के पिछड़े होने के बावजूद वे बच्चों में बेहतर पोषण स्तर प्राप्त कर सके हैं। दूसरी ओर, जब सर्वाधिक कुपोषण वाले अंतिम 5 राज्यों में महाराष्ट्र जैसा विकसित राज्य और प. बंगाल जैसा कम्युनिस्ट शासन वाला राज्य भी शामिल है। इससे स्पष्ट है कि राज्य के आर्थिक विकास और बाल कुपोषण के स्तर में कोई सीधा सम्बंध नहीं है। ऐसा होना निश्चित ही हमारी विकास नीतियों पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है।

देश के विभिन्न राज्यों के वर्ष 1992-93 के बाल कुपोषण के स्तर और वर्ष 1992-93 से 2005-06 के मध्य उसमें आई कमी के बीच सम्बंध को देखने के लिए तालिका-2 देखिए। इस तालिका में खड़े अक्ष में वर्ष 1992-93 में कुपोषण के स्तर के आधार पर राज्यों को वर्गीकृत किया है तथा आड़े अक्ष में उनमें अध्ययन अवधि में आई बाल कुपोषण के प्रतिशत में कमी के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। इस तालिका के अवलोकन से प्रकट होता है कि 1992-93 से 2005-06 की अवधि में बाल कुपोषण के स्तर में वृद्धि (ऋणात्मक कमी) वाले राज्यों में केरल, हरियाणा, मध्यप्रदेश और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। सर्वाधिक वृद्धि मध्यप्रदेश में हुई है। इस वृद्धि के कारण देश के प्रमुख 18 राज्यों में वर्ष 1992-93 में मध्यप्रदेश का क्रम नीचे से नौवां था जो 2005-06 में अंतिम हो गया है। मध्यप्रदेश में बाल कुपोषण के स्तर में कमी तो दूर, उसमें तेज़ी से वृद्धि प्रदेश के नीति

निर्धारकों के लिए बड़ी चिंता का विषय होना था, परंतु ऐसा होना तो दूर, संभवतया उन्हें इसका एहसास भी नहीं है। कुपोषण के स्तर में थोड़ी कमी ला सकने वाले राज्यों में उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात और उत्तरप्रदेश आते हैं। जिन राज्यों में बाल कुपोषण के स्तर में कमी आ सकी है, उनमें तमिलनाडु, प. बंगाल और पंजाब शामिल हैं। जहां मध्यप्रदेश में बाल कुपोषण के स्तर में वृद्धि हुई है, वहीं उससे अलग हुए राज्य छत्तीसगढ़, जो पिछड़ा भी है, अपने यहां कुपोषण के स्तर में कमी लाने में सफल रहा है। तेज़ी से उभरते राज्यों, आंध्र और कर्नाटक तथा सर्वाधिक विकसित राज्य महाराष्ट्र के साथ उड़ीसा एवं असम जैसे पिछड़े राज्य भी अपने यहां बाल कुपोषण के स्तर में मध्यम स्तर की कमी ला सके हैं।

इस विश्लेषण से जो निष्कर्ष उभरकर सामने आते हैं, वे इस प्रकार हैं। बाल कुपोषण की दृष्टि भारत की स्थिति बहुत खराब है और इसे देखते हुए शासन द्वारा इसमें कमी लाने को जो सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी थी, उसका कहीं अता-पता नहीं है। वर्ष 1998-99 से 2005-06 की अवधि में पूर्व की अवधि की तुलना में विकास दर तो बेहतर हुई है परंतु कुपोषित बच्चों के प्रतिशत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। केरल, हरियाणा, झारखंड और मध्यप्रदेश जैसे अनेक राज्यों में बाल कुपोषण में वृद्धि हो रही है। इस स्थिति में जितनी जल्दी सुधार लाया जा सके, लाना होगा। पंजाब, तमिलनाडु एवं प. बंगाल जैसे कुछ राज्यों में बाल कुपोषण के स्तर में कमी लाई जा सकी है। उनकी नीतियों का विशेष अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि उन्हें अन्य राज्यों में भी अपनाया जा सके।

अगर हम बाल कुपोषण के स्तर को आधा करने के सहस्राब्दी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो शेष बचे वर्षों में हमें बाल कुपोषण को कम करने की दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य करना होगा। ऐसा करना वर्तमान खुशहाली के अलावा भविष्य के लिए मानव संपदा को बेहतर बनाने तथा ऊंची विकास दर को सतत बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। (स्रोत विशेष फीचर्स)